पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 368/2014

थाना कांड संख्या-118 वर्ष-2010 थाना-खगड़िया जिला- खगड़िया से उत्पन्न

=====

माला देवी पत्नी स्वर्गीय अरबिंद साह निवासी ग्राम पीओ रामगंज, पुलिस स्टेशन - मुफसिल, जिला -
खगड़िया

... ..अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2014 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 297

थाना कांड संख्या-118 वर्ष-2010 थाना-खगड़िया जिला- खगड़िया से उत्पन्न

=====

राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राम शरण साह निवासी ग्राम रामगंज, थाना खगड़िया मुफसिल, जनपद
खगड़िया।

... .. अपीलकर्ता/एस

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाताओं

=====

उपस्थिति:

(2014 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 368 में)

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री अमरेंद्र कुमार, प्रतिवादी के वकील

प्रतिवादी के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

सूचनाकर्ता के लिए : श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, एडवोकेट

श्री संतोष कुमार सिंह, एडवोकेट

(2014 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 297 में)

अपीलकर्ता के लिए : श्री प्रतीक मिश्रा, अधिवक्ता

श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, एडवोकेट

प्रतिवादी के लिए : श्री वत्सल विशाल, एडवोकेट
 सूचनाकर्ता के लिए अधिवक्ता : श्री सुजीत कुमार सिंह,
 श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता
 श्री संतोष कुमार सिंह, एडवोकेट

=====

अपील – दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302, 149 और 120 बी और 201 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

आयोजित – आई.ओ. ने स्वीकार किया है कि उसके पास सी.डी.आर. की मूल प्रति नहीं है। इसके अलावा, उनके बयान के अनुसार, किसी संजय कुमार ने सी.डी.आर. की प्रति प्रदान की है। उसे। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त संजय कुमार से पूछताछ नहीं की गई है। – अभियोजन पक्ष द्वारा मोबाइल कंपनी के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई और न ही साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी(4) के तहत जारी प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया। (पैरा 28)

ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से सी.डी.आर. पर भरोसा किया है। और अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है। (पैरा 29)

अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश करके अपीलकर्ताओं की ओर से मृतक को मारने के मकसद को साबित नहीं किया है। (पैरा 29)

संहिता की धारा-313 के तहत बयान दर्ज करते समय आरोपी के सामने न रखी गई परिस्थितियों का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। (पैरा 31)

अपील की अनुमति है। (पैरा 34)

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

कोरम:माननीय श्री न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय श्री न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली)

दिनांक : 08-05-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संदर्भित) की धारा-372 के तहत दायर की गई हैं 2010 के सत्र परीक्षण संख्या 395 (2010 के खगड़िया मुफ्फसिल पीएस केस नंबर 118 से उत्पन्न) के संबंध में तदर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- II, खगड़िया द्वारा पारित दिनांक 28.02.2014 के दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 05.03.2014 को चुनौती देने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा अपीलकर्ताओं/दोषियों द्वारा दंड दिया गया है और सजा सुनाई गई है आईपीसी की धारा-302 के साथ 149 और 120 बी और 201 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक को 10,000 / - (दस हजार) रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा और आईपीसी की धारा-201 के तहत अपराध के लिए प्रत्येक तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाएगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को छह-छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है और हिरासत की अवधि को बीती हुई अवधि माना जाएगा।

2. वर्तमान को दाखिल करने के लिए अग्रणी संक्षिप्त तथ्य अपील निम्नानुसार हैं:

न्यायाधीश ने कहा, '16 अप्रैल 2010 को रात करीब 12 बजे सूचना देने वाले के भाई प्रशांत कुमार के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई, लेकिन जब वह घर से निकला तो परिवार वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह वापस नहीं लौटा. उस पर प्रशांत कुमार इतने सारे बच्चों के बीच किशोर साह के चबूतरा पर सो रहे थे। परिवार के सदस्य सुबह से ही उसके ठिकाने की तलाश में लगे हुए हैं। जिस मोबाइल फोन पर कॉल रिसीव हुई थी, वह स्विच ऑफ है। मुखबिर ने अपने परिवार के सदस्यों और परिचितों के साथ मिलकर अपने भाई प्रशांत कुमार की गहन खोज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुखबिर को आशंका है कि प्रशांत कुमार को अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर लिया है।

3. एफआईआर दर्ज करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए

मामला सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध था जहां इसे 2010 के सत्र परीक्षण संख्या 395 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

4. विद्वान वकील श्री अमरेंद्र कुमार प्रस्तुत करते हैं कि, शुरु में, उन्होंने दायर किया था अपीलकर्ता माला देवी की ओर से वकालतनामा। हालांकि, इसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उससे कागजात वापस ले लिए हैं और उसने कोई आपत्ति नहीं दी है। हालांकि, आज तक वर्तमान अपीलकर्ता की ओर से किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। यह ध्यान रखना उचित है कि वर्तमान अपील 2014 से लंबित है और अपीलकर्ता महिला दोषी 29 अप्रैल, 2010 से हिरासत में है और इसलिए, हमने विद्वान वकील श्री अमरेंद्र कुमार से इस मामले में सहायता करने का अनुरोध किया है। जैसा कि अतीत में उन्होंने वर्तमान अपीलकर्ता की ओर से उपस्थिति दर्ज की थी, उन्होंने अदालत के उक्त अनुरोध को आसानी से स्वीकार कर लिया है और इस मामले में अदालत की सहायता की है।

5. अपीलकर्ताओं के लिए श्री बीरेंद्र कुमार सिंह और श्री वत्सल विशाल द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वकील श्री अमरेंद्र कुमार और श्री प्रतीक मिश्रा, प्रतिवादी राज्य की ओर से श्री सुजीत कुमार सिंह, विद्वान एपीपी और श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल और संतोष कुमार सिंह, सूचनाकर्ता के लिए विद्वान वकील सुने गए।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिनसे यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को मार डाला है।

6.1. इस स्तर पर, विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले से, 16.04.2010 को, रात लगभग 12:00 बजे, मुखबिर के भाई को उसके मोबाइल फोन पर कॉल किया और उसके बाद वह घर से निकला और वापस नहीं लौटा। सूचना देने वाले के भाई का फोन आया तो वह किशोर साह के चबूतरा पर जाने का आश्वासन देकर निकला और 2-3 घंटे बाद लौट आया, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने मुखबिर के भाई की तलाश की है। हालांकि, उसका पता नहीं चल सका और इसलिए मुखबिर द्वारा पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद यह आरोप लगाया गया है कि मृतक का शव एक आरोपी के सेप्टिक टैंक में पाया गया था।

6.2. इस स्तर पर, यह बताया गया है कि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभियुक्त के इकबालिया बयान दर्ज किए जाने के बाद अभियुक्त के उदाहरण पर शव की खोज की गई थी। रिकॉर्ड से

यह बताया गया है कि उक्त कहानी सही नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि शव 27.04.2010 को बरामद किया गया था जबकि दोनों आरोपी अपीलकर्ताओं को 29.04.2010 को गिरफ्तार किया गया था।

6.3. विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सीडीआर के आधार पर, पुलिस अपीलकर्ता/अभियुक्त माला देवी के घर पहुंची। जब वह उत्तर प्रदेश में थी, तो उसे उत्तर प्रदेश से रामगंज लाने के लिए, एक पुलिस कांस्टेबल रमाकांत सिंह को जांच अधिकारी द्वारा भेजा गया था और यह आरोप लगाया गया है कि जब उसे उक्त पुलिस कांस्टेबल द्वारा ट्रेन में लाए जाने पर माला देवी द्वारा स्वीकारोक्ति की गई थी कि उसने अन्य दो आरोपियों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की है और उसके शव को अरविंद साह के सेप्टिक टैंक में रखा गया है।

6.4. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद सह-अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता का इकबालिया बयान जांच अधिकारी द्वारा 24.04.2010 को दर्ज किया गया था। हालांकि उससे पहले ही मृतक का शव घटना स्थल से बरामद कर लिया गया था। विद्वान अधिवक्ताओं ने पी.डब्ल्यू. उक्त पैराग्राफ में उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि शव बरामद किया गया था और उसके बाद पुलिस उक्त स्थान पर आई थी। विद्वान वकीलों ने पीडब्ल्यू 4 अर्चना देवी द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख किया है, विशेष रूप से पैरा -22, जिसमें उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि शव बरामद होने के बाद, अभियुक्तों के नामों का खुलासा किया गया था।

6.5. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि 27.04.2010 को अपीलकर्ताओं के इकबालिया बयान दर्ज करते समय भी, वे पुलिस हिरासत में नहीं थे और वे उक्त तारीख को आरोपी नहीं थे और इसलिए भी, शव की तथाकथित खोज साक्ष्य अधिनियम की धारा -27 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। एआईआर 1966 एससी 119 में रिपोर्ट किए गए अघनू नगेशिया बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर निर्भरता। यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच अधिकारी ने पंचनामा तैयार नहीं किया है और खोज किए जाने से पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। इस स्तर पर, विद्वान वकीलों ने रामानंद @ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जो एआईआर 2022 एससी 5273 में रिपोर्ट किया गया है। विद्वान वकीलों ने एआईआर 2022 एससी 5110 में रिपोर्ट किए गए सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है।

6.6. इसके बाद अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया कि सीडीआर की मूल प्रति भी अदालत के समक्ष पेश नहीं की गई थी। केस डायरी का केवल प्रासंगिक हिस्सा जांच अधिकारी द्वारा संदर्भित किया गया था और यह आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि

साक्ष्य अधिनियम की धारा -65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र भी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश नहीं किया गया था और इसलिए भी, सीडीआर विधिवत साबित नहीं हुआ है। इस स्तर पर, यह भी बताया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, उसे उक्त संजय कुमार से सी.डी.आर. हालांकि, उक्त संजय कुमार अभियोजन पक्ष द्वारा से भी पूछताछ नहीं की गई है। **2022 लाइव लॉ (एससी) 461 में रिपोर्ट किए गए रविंदर सिंह @ काकू बनाम पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।**

6.7. इसके बाद, विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि यहां तक कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों को भी संहिता की धारा -313 के तहत अपना बयान दर्ज करते समय उनके सामने नहीं रखा गया था। इसलिए, विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि **एआईआर 2013 एससी 3817 में रिपोर्ट किए गए सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसी परिस्थितियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।**

6.8. इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने तर्क दिया कि हालांकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं/दोषियों के खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाना चाहिए और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

7. दूसरी ओर, मुखबिर के विद्वान वकील और विद्वान एपीपी ने वर्तमान अपीलों का विरोध किया है। यह मुख्य रूप से तर्क दिया जाता है कि, हालांकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, अभियोजन पक्ष ने जिन परिस्थितियों से यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किए हैं। उत्तरदाताओं के विद्वान वकीलों ने मृतक और वर्तमान अपीलकर्ताओं के मोबाइल फोन के सीडीआर पर भरोसा किया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं के इकबालिया बयान के आधार पर, मृतक का शव अरविंद साह के सेप्टिक टैंक से खोजा गया था। ऐसी खोज साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के मद्देनजर साक्ष्य में स्वीकार्य है। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की गई है और इसलिए, इन दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 20 गवाहों का परीक्षण किया है। इस स्तर पर, हम ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में प्रासंगिक सबूतों की सराहना करना चाहेंगे।

9. पी.डब्ल्यू. 1 लक्ष्मण कुमार सह-ग्रामीण हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत को करीब एक साल पहले ही मार दिया गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे। पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया।

10. पीडब्ल्यू 2 फकीर कुमार ने यह भी गवाही दी है कि वह प्रशांत को जानता था जिसे मार दिया गया है, लेकिन वह नहीं जानता कि कैसे।

11. पी.डब्ल्यू. 3 उर्मिला देवी मृतक प्रशांत की माता है। उसने कहा है कि घटना लगभग 15 महीनों हुई थी। रात 9:00 बजे उनका बेटा प्रशांत खाना खाने के बाद यह कहकर निकला था कि वह जल्द आएगा, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इसके बाद वह सो गई। वह सुबह भी नहीं लौटा। इसके बाद घरवालों ने उसकी तलाशी शुरू की। उन्होंने बताई गई जगह की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। जब प्रशांत का पता नहीं चल सका तो उसके बड़े बेटे मनोज कुमार ने थाने में मामला दर्ज कराया। 11-12 दिन बाद उसके बेटे का शव पुलिस ने अरविंद साह के सेप्टिक टैंक से बरामद किया। वह उस स्थान पर गई थी और उसने अपने बेटे के शव को चाकू से बने चाकू के घाव और गले में बंधी साड़ी के निशान के साथ देखा था। उसने कहा है कि आरोपी अरविंद साह, उसकी पत्नी माला देवी, पिता राजेश ने उसके बेटे की हत्या कर दी है, जिसे वह घटनास्थल पर उपलब्ध लेखों की मदद से पहचानती है। उसने अरविंद, रघुनाथ, राजेश और माला देवी की पहचान करने का दावा किया है।

11.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि चूंकि उसका बयान उसके बेटे के शव की बरामदगी से पहले दर्ज किया गया था, इसलिए उसने अपने बयान में इसका उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि अरविंद साह अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उसने कहा है कि अरविंद और उसके पिता पेशे के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं। वह इस बात से इनकार करती है कि माला देवी अपने पति के साथ दूसरी जगह रहती है। उन्होंने आगे कहा है कि उनका बेटा प्रशांत एक होटल चलाता था और कभी-कभी वहीं रहता था। उसने यह भी कहा है कि अरविंद, उसके पिता और माला से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। शव से दुर्गंध आ रही थी। शव की शिनाख्त होने की हालत में था और वह सूज गया था। उनका दावा है कि प्रशांत का शव अरविंद के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। इसलिए उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने ही प्रशांत की हत्या की है। उसने नहीं देखा था कि उसका बेटा किसके साथ गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जिस टैंक से शव बरामद किया गया था, वह अरविंद का नहीं है।

11.2. अपनी जिरह में, उसने आगे कहा है कि उसके तीन बेटों, अर्थात् मनोज, सतीश और प्रशांत में से सतीश भी मारा गया है। पूरे गांव में इस संदेश के फैलने के बाद पुलिस पहुंची थी। जब वह प्रशांत की पत्नी के साथ शव के पास पहुंची तो वहां सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। प्रशांत का शव घर नहीं लाया गया बल्कि पुलिस अपने साथ ले गई थी। उस समय आरोपियों के नाम सामने नहीं आए थे। प्रशांत का

शव मिलने के बाद वह कभी किसी पुलिसकर्मी से नहीं मिली। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि गांव की राजनीति के कारण राजेश का नाम आरोपी के रूप में लिया गया था। उसने झूठी गवाही देने से इनकार किया है।

12. पी.डब्ल्यू-4, अर्चना देवी मृतक प्रशांत की पत्नी है। उसने गवाही दी है कि उसका पति, दुकान से लौटने के बाद, किशोर साह के पक्के (पक्के आयताकार मंच) पर आराम करने के लिए गया था और उसे 2-3 घंटे बाद आने का आश्वासन दिया था लेकिन उसका पति वापस नहीं आया। घटना के अगले दिन अरविंद साह के एक सेप्टिक टैंक से उसके पति की चप्पल और दूसरे से शव बरामद किया गया। शव नग्न था, गले में साड़ी बंधी हुई थी और चाकू का घाव था। उसका दावा है कि आरोपी अरविंद साह, माला देवी, रघुनाथ साह और राजेश साह ने उसके पति की हत्या कर शव को छिपा दिया। वह अदालत में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने का दावा करती है। अपनी जिरह में, उसने कहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज करने से पहले उससे पूछताछ की थी। वह यह नहीं कह सकती कि पुलिस ने उसके बताए अनुसार बयान दर्ज किया या नहीं। इस गवाह द्वारा आगे यह गवाही दी गई है कि वह अपने पति के शव की बरामदगी की तारीख नहीं बता सकती है। पैरा-22 में उसने कहा है कि उसने पुलिस के सामने बताया था कि उसके पति की चप्पलें अरविन्द साह के एक सेप्टिक टैंक से और दूसरे सेप्टिक टैंक से उसके पति का शव बरामद किया गया। उसने पुलिस के सामने बताया था कि शव के गले में साड़ी बंधी हुई थी, शव नग्न था और आरोपी अरविंद साह, माला देवी, रघुनाथ साह और राजेश ने मिलकर उसकी हत्या की थी और शव को टैंक में धकेल दिया था। आरोपियों के नाम शव मिलने के बाद खुलासा हुआ। उसने इस बात से इनकार किया है कि शव पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। वह शरीर के उन हिस्सों को इंगित नहीं कर सकती जिनमें घाव हैं। उसे नहीं पता कि शव का कोई अंग अलग हुआ था या नहीं। उसने कहा है कि उसके पति की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने उसे पढ़ाया हुआ बयान दिया है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसके पति का आचरण दोषपूर्ण नहीं था, जिसके कारण उसे मार दिया गया है।

13. पी.डब्ल्यू-5, पंकज कुमार एक सुनी-सुनाई गवाह है जिसने अपनी परीक्षा में गवाही दी है कि 16.04.2010 को रात्रि 09:30 बजे प्रशांत कुमार किशोर साह के चबूतरा पर बैठा था। यह साक्षी भी पैदल चलते-चलते वहां पहुंच गई। उन्होंने प्रशांत कुमार से कुछ देर बात की और रात करीब 10:00-10:15 बजे वहां से चले गए। सुबह उसे पता चला कि प्रशांत लापता है जिसके लिए मनोज कुमार ने केस दर्ज कराया है। दिनांक 27.04.2010 को सायं 04:00-05:00 बजे के बीच पुलिस अरविन्द साह और रघुनाथ के घर आई। प्रशांत का शव अरविंद साह के नवनिर्मित घर के निष्क्रिय सेप्टिक टैंक से बरामद किया

गया। अरविंद साह के पहले टैंक से मृतक प्रशांत कुमार की चप्पलें बरामद की गईं। अरविंद और माला देवी के घर से, एक टी-शर्ट, साड़ी का 1/2 हिस्सा बरामद किया गया। साड़ी का आधा हिस्सा खून से सना हुआ था और दूसरा आधा प्रशांत कुमार के गले में बंधा हुआ था। उसने दावा किया है कि शव नग्न था और अरविंद साह, माला देवी और रघुनाथ साह ने प्रशांत कुमार की हत्या की थी। उन्होंने कटघरे में मौजूद अरविंद साह, माला देवी, राजेश गुप्ता, रघुनाथ साह और किशोर साह की पहचान की।

13.1. अपनी जिरह में इस गवाह ने कहा है कि प्रशांत कुमार उसका दोस्त था। उन्होंने अरविंद साह, माला देवी, रघुनाथ साह, किशोर साह और राजेश गुप्ता की पहचान ग्रामीण के रूप में की। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शव को पानी रहित टैंक के बाहर देखा था। शव को बरामद करने के लिए टैंक से जुड़े नल को उखाड़ दिया गया था। चूंकि टैंक अरविंद साह का था, इसलिए उसे संदेह है कि अरविंद साह, माला देवी और रघुनाथ साह अपराध के पीछे थे। वह यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकता कि टैंक अरविंद साह का था। उन्होंने आगे कहा है कि शव पहचान के योग्य था। यह कहना गलत है कि शव सड़ चुका था और उसे बाहर खींचने के दौरान उसके अंग अलग हो गए थे। अपनी जिरह के पैरा-13 में उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के पैरा-1 में दिए गए अपने बयानों का खंडन किया है और अपनी जिरह के पैरा-14 में उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के पैरा-2 में दिए गए अपने बयानों का समर्थन किया है। उसने कोर्ट में मनोज कुमार से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने मनोज कुमार के निर्देश पर झूठी गवाही दी है, जो घटना के वास्तविक कारण को छिपाना चाहते थे।

14. पी.डब्ल्यू.-6, सुबोध कुमार साह ने बताया है कि 17.04.2010 को यह घटना हुई थी। वह अपने घर पर था। सुबह के 07:00 बज रहे थे अरविंद साह उनके घर आए और बताया कि उन्हें चोट लगी है। अरविंद साह के बाएं गाल पर चोट लगी थी और उनका एक दांत टूट गया था। उसने घाव पर मरहम पट्टी की, डेटॉल लगाया और उसे लेने के लिए दो गोलियां दीं। उसके बाद गवाह अपने ससुराल (ससुराल) गया और लौटने पर उसे पता चला कि प्रशांत अब नहीं रहा।

14.1. अपनी जिरह में, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वह एक झोला छल डॉक्टर हैं। उसने स्वीकार किया है कि उसने अरविंद को गोलियां दी थीं, जो वह घर पर रखता है। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस ने उनका बयान दर्ज नहीं किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने अरविंद के साथ व्यवहार करने के लिए गलत बयान दिया था। वह स्वीकार करता है कि उसके पास योग्यता की कोई डिग्री नहीं है।

15. पी.डब्ल्यू.-7 डॉ. जगदेव मंडल ने बताया है कि दिनांक 27.04.2010 को जब वे सदर अस्पताल, खगड़िया में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 27-04-2010 को एक चिकित्सा

बोर्ड पत्र संख्या 722 दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के माध्यम से डीएम, खगड़िया के आदेश द्वारा गठित किया गया। (खगड़िया) ग्राम रामगंज मुफ्फसिल के 35 वर्षीय पुत्र रामजी साह के शव की जांच के लिए डा रवीन्द्र नारायण, डा केएन प्रसाद और मैं जगदेव मंडल नामक निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए दिनांक 27-04-2010 को एक विशेष समिति का गठन किया गया है। गठित बोर्ड ने दिनांक 27-04-2010 को रात्रि 9:00 बजे शव का पोस्टमार्टम किया जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गई :-

1. बाहरी जांच करने पर, चेहरा और पूरा शरीर सूज गया था और विकृत हो गया था, विघटित हो गया था और दुर्गंध आ रही थी। जीभ बीच में निकली हुई थी, होंठ सूजे हुए थे और पूरे शरीर पर मैगोट मौजूद था। शरीर के विभिन्न हिस्सों में त्वचा की पीलिंग थी। गर्दन के चारों ओर एक व्यापक संयुक्ताक्षर मौजूद था, चौड़ाई में लगभग 3", क्षैतिज और गर्दन के दाईं ओर गाँठ के साथ निरंतर। और हटाने पर संयुक्ताक्षर के निशान तक (अस्पष्ट)।

2. के पीछे एक चाकू का घाव $1 \times 1/2 \times 1/4$ ऊपरी बांह छोड़ दिया।

3. एक छुरा घाव $3 \times 1/2 \times$ गुहा गहरी पर पेट के ऊपरी भाग के दाईं ओर पार्श्व पक्ष जिसके माध्यम से छोटी आंत का एक लूप निकलता है।

4. दाहिनी निचली छाती के पार्श्व पक्ष पर $1 \times 1/2 \times$ गुहा गहरा घाव करें।

5. आकार में ऑक्सिला $1 \times 1/2 \times 1$ के नीचे लगभग 10" अक्षीय रेखा पर छाती के बाईं ओर के पार्श्व पक्ष को छुरा घाव करें।

6. चोट नंबर 5 के नीचे लगभग 2" मध्य एक्सिलरी लाइन में छाती के पार्श्व पक्ष पर $1/2 \times 1/2 \times 1/2$ चाकू घाव।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखी गई है और यह किसी जगह फटी हुई (गड्ढा) है . इसलिए वह पढ़ने में असमर्थ है । उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर (एक्स-1) के रूप में हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की है।

16. पी.डब्ल्यू. 16 डॉ. रवीन्द्र नारायण ने भी पी.डब्ल्यू. 7 के उक्त संस्करण का समर्थन किया है।

17. पी.डब्ल्यू.-8 मनोज कुमार ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि वह मामले का मुखबिर है। वह 16-04-2010 की रात को घर पर था। रात करीब 9:00-10:00 बजे उसका भाई प्रशांत कुमार अपनी मां और पत्नी को लौटने का आश्वासन देते हुए किशोर साह के चबूतरा में आराम करने के लिए चला गया। साक्षी सुबह उठी तो उसकी मां उर्मिला देवी ने बताया कि प्रशांत वापस नहीं लौटा। उसने

मोबाइल नंबर 9472076386 और 9308592424 पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह स्विच ऑफ था। वह किशोर साह के चबूतरा में गया और चबूतरा पर सो रहे फकीर कुमार, ललन कुमार, ऋषि कुमार, ऋतु कुमार से पूछा जिन्होंने उन्हें बताया कि रात 12:00 बजे एक महिला का फोन आया और प्रशांत बाहर चला गया, लेकिन वे सही समय नहीं बता सकते। जब काफी खोजबीन के बावजूद प्रशांत का पता नहीं चल सका तो उसने थाने में अपनी कलम और हस्ताक्षर (एक्स-2) में लिखित आवेदन जमा किया। उन्होंने आगे कहा है कि दिनांक 27-04-2010 को पुलिस राजेश कुमार गुप्ता के साथ अरविन्द साह के घर गई थी। वह और प्रशांत की पत्नी भी वहां पहुंच गए। राजेश कुमार द्वारा दिए गए सुराग पर अरविंद साह के भाई प्रशांत के सेप्टिक टैंक से एक जोड़ी चप्पल बरामद की गई। आंगन से एक बोरा भी बरामद किया गया, जिसमें से एक सूती गद्दा, खून से सना लाल रंग का आधा साड़ी, खून से सना आधा पैंट और खून से सना हरा रंग का ब्लाउज बरामद किया गया। प्रशांत का शव नग्न हालत में अरविंद साह के निष्क्रिय टैंक से बरामद किया गया। छाती का बायां हिस्सा चोट से सूज गया था और साड़ी का आधा हिस्सा बरामद किया गया था जिससे गर्दन बंधी हुई थी और साड़ी का आधा हिस्सा बोरे से बरामद किया गया था। इसलिए गवाह को इस बात की प्रबल आशंका है कि राजेश गुप्ता, अरविंद साह, माला देवी और रघुनाथ साह ने साझा इरादे से उसके भाई की हत्या की थी। वह अदालत में मौजूद चारों की पहचान करता है। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि किशोर साह को झूठा फंसाया गया है।

17.1. अपनी जिरह में, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि अरविंद और माला देवी 16.04.2010 को खगड़िया में नहीं थे। उन्होंने आगे कहा है कि उनके शव की बरामदगी से पहले उन्हें प्रशांत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने बरामद होने के बाद शव बरामद होने की जगह पर उसे बुलाया। पुलिस ने शव उन्हें नहीं सौंपा, बल्कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा है कि यह सच नहीं है कि शव पहचान के योग्य नहीं था। उसने कहा कि वह शव के साथ अस्पताल गया था। शव को करीब 6-7 बजे अस्पताल ले जाया गया, थाने में नहीं। वह करीब 1-2 घंटे तक शव के पास रहा। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जब पुलिस को प्रशांत की हत्या में उनका हाथ होने का संदेह था, तो उन्होंने संदेह को आरोपी व्यक्तियों की ओर मोड़ दिया।

18. पी.डब्ल्यू. 9 संजीव कुमार, पी.डब्ल्यू.10 बेचन शाह, पी.डब्ल्यू. 11 विजय कुमार और पी.डब्ल्यू. 12 सुबोध कुमार साह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्ष द्रोही हो जाने की घोषणा की गई है।

19. पी.डब्ल्यू. 13 संजय कुमार राय वर्तमान मामले के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि 21.04.2010 को उन्हें खगड़िया (मुफ्फसिल) पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. के रूप में तैनात किया

गया था। मनोज कुमार ने 21-04-2010 को 14:30 बजे एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी कलम और हस्ताक्षर में अग्रोषण पत्र लिखा जिसे वह पहचानते हैं। इसे एक्सटेंशन-3 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने खुद मामले की जांच का जिम्मा संभाला। थाने में ही उसने मुखबिर मनोज कुमार का पुनः बयान दर्ज किया और उसके साथ घटना स्थल के लिए आगे बढ़ा। पैरा-3 में उन्होंने घटना स्थल का विस्तृत विवरण दिया है। इसके बाद उन्होंने फकीर कुमार, लक्ष्मण कुमार, अर्चना देवी और उर्मिला देवी के बयान दर्ज किए। 22.04.2010 को उन्होंने उसने मोबाइल नंबर 9308592424 और 9472076386 के कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर पुलीस अधीक्षक संजय कुमार और मोबाइल कंपनी को आवेदन दिया। दिनांक 23-04-2010 को मोबाइल नंबरों के कॉल ब्यौरे प्राप्त किए गए थे। उन्होंने मोबाइल नंबर 9472076386 की कॉल डिटेल की जांच की तो पाया कि इस नंबर से 7-8 बार मोबाइल नंबर 9279189126 पर किए गए थे। उन्होंने केस डायरी के पैरा -28 में कॉल की सामग्री का विवरण दिया है जो उनकी लिखावट में है और वह उसी की पहचान करते हैं (एक्सटेंशन -5)। प्रशांत के दूसरे मोबाइल से कॉल की सामग्री निकाली गयी तो उत्तर हाजीपुर खगड़िया के सुरेंद्र कुमार के नंबर 9279189126 का विवरण केस डायरी (एक्सएच-6) के पैरा-29 में दिया गया है। उन्होंने केस डायरी (एक्सटेंशन-7) के पैरा-36 में 16.04.2010 और 17.04.2010 को मोबाइल फोन पर की गई बातचीत का विस्तृत ब्यौरा दिया है।

19.1. दिनांक 03.11.2012 को अपने आगे के बयान में उन्होंने कहा है कि सुरेंद्र कुमार के मोबाइल नंबर से प्रशांत कुमार के दोनों मोबाइल नंबरों पर घटना की रात बार-बार कॉल आ रही है। दिनांक 17-04-2010 को 17:46 बजे के पश्चात् प्रशांत कुमार के मोबाइल फोन पर कोई इनकमिंग अथवा आउटगोइंग कॉल नहीं है। सुरेंद्र कुमार का मोबाइल फोन भी बंद है। कॉल डिटेल 15-04-2010 से 24-04-2010 तक का है प्रशांत कुमार भी 16-04-2010 को रात 12:00 बजे मोबाइल फोन पर बात करने के बाद लापता है और उसका मोबाइल फोन बंद कर दिया। उन्होंने केस डायरी (एक्सटेंशन-9) के पैरा-40 में प्रशांत और सुरेंद्र कुमार के बीच हुई बातचीत का ब्योरा दिया है। पूछताछ करने पर, सुरेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने मोबाइल नंबर 9279189126 खरीदा था और इसे अपनी पत्नी की बड़ी बहन, माला देवी, पत्नी अरविंद साह को उपहार में दिया था। खरीदी के बाद से ही उक्त मोबाइल माला देवी के अनन्य उपयोग में है। वह अपने पति के साथ उत्तर प्रदेश में हैं। वह 20-04-2010 को उत्तर प्रदेश गई थी।

19.2. गवाह ने आगे कहा कि जब उसने रघुनाथ साह से पूछताछ की, तो उसने कहा कि अरविंद साह उसका बेटा था। वह (अरविंद साह) 16.04.2010 को आए और 20.04.2010 को अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले गए। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने प्रशांत कुमार के वाहन नंबर बीआर-340893 के चालक सुबोध कुमार, पीडब्ल्यू 11 का बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा है कि प्रशांत कुमार

माला देवी को अपने होटल में लाते थे। माला देवी का कई अन्य लोगों से भी संपर्क था। पी.डब्ल्यू. 9 संजीव कुमार ने भी पी.डब्ल्यू.11 का ही लाइन दोराया ।

19.3. उन्होंने आगे कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति के बाद, ए.एस.आई रमाकांत सिंह और चौकीदार 9/12 महेश साह को शाहजहांपुर भेजा गया था। पता चला कि मोबाइल नंबर 970978415 राजेश कुमार का है। आगे पूछताछ करने पर, उसने अपना इकबालिया बयान दिया जो उनकी कलम और हस्ताक्षर (Ext-10) में है। राजेश कुमार गुप्ता के इकबालिया बयान के आधार पर उन्होंने घटना स्थल पर छापा मारा और अरविंद साह के सेप्टिक टैंक से चप्पल बरामद कर जब्त कर जब्ती सूची तैयार की। प्रशांत कुमार की पत्नी ने प्रमाणित किया कि वही प्रशांत कुमार (एक्सटेंशन-11) का है।

19.4. उन्होंने आगे कहा है कि एएसआई रमाकांत सिंह ने मोबाइल फोन पर सूचित किया कि माला देवी को खगड़िया लाते समय रास्ते में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और कहा है कि प्रशांत का शव उसके घर के निष्क्रिय सेप्टिक टैंक के किनारे पड़ा है और प्रशांत के कपड़े आंगन में एक बोरे में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले पत्तों के ढेर के नीचे रखे हुए हैं। उसी दिन 16:30 बजे, राजेश कुमार गुप्ता और माला देवी के इकबालिया बयानों के आधार पर टैंक का आवरण हटा दिया गया और दुर्गंध आने लगी और बाद में शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान मृतक के परिवार के सदस्यों ने की। उन्होंने रविंद्र कुमार और मुन्ना कुमार (एक्सटेंशन-12) द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति की पहचान की है।

19.5. उन्होंने पैरा-49 में आगे कहा है कि पैरा-72 में वर्णित कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि किसकी साड़ी और किसकी पैंट बरामद की गई। उसे नहीं मिला था

उक्त लेखों की जांच विधि विज्ञान विशेषज्ञ से की गई है। पैरा-50 में उन्होंने विशिष्ट रूप से कहा है कि उन्हें जांच के दौरान घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। उन्होंने स्वीकार किया है कि रमाकांत सिंह चौकीदार महेश साह, माला देवी और अरविंद साह के साथ ट्रेन से आए थे।

19.6. अभियुक्त किशोर साह की ओर से अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि उनके पास कॉल डिटेल्स की मूल प्रति नहीं है। उन्होंने केस डायरी में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर सीडीआर के बारे में गवाही दी है । वह केस डायरी में उल्लिखित कॉल डिटेल्स की प्रति देने में असमर्थ है। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर संजय कुमार का बयान दर्ज करने से इनकार किया है। संजय कुमार ने उन्हें मोबाइल नंबर 9279189126 के मालिक का नाम नहीं बताया था। उन्होंने कहा है कि केस डायरी में राजेश कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के

समय का उल्लेख नहीं है। उन्होंने केस डायरी के पैरा-71 में राजेश गुप्ता के घर आने की बात कही है। इससे पहले उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वह 27.04.2010 को शाम 07:30 बजे राजेश कुमार गुप्ता के घर पहुंचा था। उन्होंने यह भी कहा है कि वह दिनांक 27-04-2010 को सायं 05:00 बजे घटना स्थल पर गए थे। इससे पहले वह मोबाइल फोन (केस डायरी के पैरा-64) पर ए.एस.आई. रमाकांत सिंह से बात कर चुके थे।

19.7. पैरा -59 में, उन्होंने कहा है कि राजेश कुमार गुप्ता के परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं करें। उन्होंने राजेश कुमार गुप्ता का गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार नहीं किया वह जानते हैं कि आरोपी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना है। उन्होंने 29.04.2010 को राजेश कुमार गुप्ता को अदालत में भेजा। केस डायरी में कोई अग्रोषण पत्र उपलब्ध नहीं है।

19.8. पैरा-62 में उन्होंने कहा है कि घटना स्थल का दौरा करने के 2:30 घंटे बाद वह राजेश कुमार गुप्ता के घर पहुंचे थे। उन्होंने ए.एस.आई. रमाकांत सिंह का कोई बयान दर्ज नहीं किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि राजेश कुमार गुप्ता ने उनके सामने कोई इकबालिया बयान नहीं दिया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि राजेश कुमार गुप्ता का इकबालिया बयान फर्जी है और जांच दोषपूर्ण है।

20. पी.डब्ल्यू. 14 से 20 के बयानों को विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने विभिन्न दस्तावेजों, हस्ताक्षरों और प्रदर्शनों को साबित किया है और अपराध में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की जटिलता के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

21. हमने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में प्रासंगिक सबूतों की फिर से सराहना की है। हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों पर भी विचार किया है।

22. रिकॉर्ड से यह सामने आएगा कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और इसलिए, अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है। रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि सूचना देने वाले द्वारा दायर की गई एफआईआर की रिकॉर्डिंग के बाद, जांच अधिकारी ने लापता प्रशांत कुमार के मोबाइल फोन का विवरण एकत्र किया और उसके बाद पता चला कि प्रशांत कुमार को एक विशेष मोबाइल फोन नंबर से फोन आया था। इसलिए, यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि जांच अधिकारी ने लापता व्यक्ति यानी प्रशांत कुमार के साथ-साथ अपीलकर्ता माला देवी के मोबाइल फोन नंबर का सीडीआर एकत्र किया। यह पता चला कि वह अन्य सह-आरोपियों के संपर्क में थी। इसलिए, जांच अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में अपीलकर्ता माला देवी के स्थान पर एक पुलिस कांस्टेबल रमाकांत सिंह को

भेजा। आरोप है कि उत्तर प्रदेश से लौटते समय ट्रेन में रमाकांत सिंह के साथ उक्त माला देवी उक्त पुलिस कांस्टेबल के समक्ष इकबालिया बयान दिया कि उसने अन्य दो आरोपियों की मदद से प्रशांत कुमार की हत्या की थी। इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि माला देवी द्वारा पुलिस कांस्टेबल रमाकांत सिंह के समक्ष इकबालिया बयान दिया गया था। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि रमाकांत सिंह ने जांच अधिकारी ने उक्त इकबालिया बयान के बारे में बताया और इसलिए, उसी तारीख को यानी 27.04.2010 को, अन्य सह-अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता को पुलिस द्वारा बुलाया गया था और यह आरोप लगाया गया है कि उक्त आरोपी ने जांच अधिकारी के समक्ष इकबालिया बयान दिया था। . हालांकि, रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि रमाकांत सिंह, जिनके सामने माला देवी ने इकबालिया बयान दिया था, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। इसलिए, माला देवी द्वारा उक्त कांस्टेबल के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत या सिद्ध नहीं किया गया है। यह भी पता चला है कि ये दोनों व्यक्ति दिनांक 27-04-2010 को अभियुक्त नहीं थे। यह सच है कि उन्हें 29-04-2010 को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, मृत शरीर की खोज पहले ही की जा चुकी थी। पैराग्राफ -19 में पीडब्ल्यू 3 ने विशेष रूप से कहा है कि शव की बरामदगी का संदेश पूरे गांव में फैलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर आई थी और गांव में हमलावरों के नामों का कोई खुलासा नहीं किया गया था। इसी तरह पैराग्राफ-22 में पीडब्लू 4 में कहा गया है कि शव मिलने के बाद ही हमलावरों के नाम सार्वजनिक हो गए।

23. इस प्रकार, पूर्वोक्त साक्ष्य से, यह पता चलता है कि पुलिस के घटना स्थल पर आने से पहले, शव पहले ही बरामद हो चुका था और जब पुलिस घटनास्थल पर आई थी आरोपियों के नाम ज्ञात नहीं थे।

24. इस स्तर पर, हम साक्ष्य अधिनियम की धारा -27 का उल्लेख करना चाहते हैं जो निम्नानुसार है:

"27. अभियुक्त से प्राप्त कितनी जानकारी साबित की जा सकेगी--परंतु जब किसी तथ्य को किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजा गया है, तो ऐसी इतनी अधिक जानकारी, चाहे वह संस्वीकृति के बराबर हो या नहीं, जो इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है।

25. इस स्तर पर, हम रामानंद @ नंद लाल (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहते हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 52 से 55 में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"52. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 इस प्रकार**पढ़ता है:**

"27. अभियुक्त से प्राप्त कितनी जानकारी साबित की जा सकेगी--परंतु जब किसी तथ्य को किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजे गए रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी इतनी जानकारी, चाहे वह संस्वीकृति के बराबर हो या नहीं, जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है।"

53. यदि, यह जांच अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि आरोपी अपीलकर्ता ने अपनी मर्जी से और स्वेच्छा से हिरासत में रहते हुए एक बयान दिया कि वह उस जगह पर ले जाएगा जहां उसने अपने खून से सने कपड़ों के साथ अपराध के हथियार को छिपा दिया होता तो जांच अधिकारी को सबसे पहले थाने में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए था। एक बार जब दो स्वतंत्र गवाह अपनी उपस्थिति में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो अभियुक्त को एक उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वह उस स्थान को इंगित करने के संबंध में चाहता है जहां उसने अपराध के हथियार को छिपाया है। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष इस तरह का बयान देता है, तो सटीक बयान या अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो जांच अधिकारी कानून के अनुसार निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास किया जा सके कि अभियुक्त द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा से उस स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक विशेष बयान दिया गया था जहां अपराध के हथियार या अपराध के कमीशन में किसी अन्य वस्तु का उपयोग किया गया था छुपाया गया था। एक बार पंचनामा का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद, पुलिस पार्टी आरोपी और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाह) के साथ आरोपी के नेतृत्व में विशेष स्थान पर आगे बढ़ेगी। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु जैसी कोई चीज खोजी जाती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामा का दूसरा हिस्सा होगा। इस तरह कानून जांच अधिकारी से अपेक्षा करता है कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज पंचनामा तैयार करे। यदि हम जांच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि मामले के उपरोक्त सभी प्रासंगिक पहलुओं में इसकी कमी है।

54. यही कारण है कि हम तैयार नहीं हैं या अनिच्छुक नहीं हैं इस बात का प्रमाण यह है कि जांच अधिकारी ने अपने मौखिक साक्ष्य में आरोपी द्वारा थाने में कहे गए सटीक शब्दों के बारे में नहीं कहा है। खोज के साक्ष्य को खारिज करने का दूसरा कारण यह है कि जांच

अधिकारी खोज पंचनामा की सामग्री को साबित करने में विफल रहा है। साक्ष्य को खारिज करने का तीसरा कारण यह है कि भले ही जांच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को जस का तस स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन जो कमी है वह है छुपाने का लेखकत्व। खोज के साक्ष्य को खारिज करने का चौथा कारण यह है कि यद्यपि पंच गवाहों में से एक पीडब्लू-2, छत्रपाल रैदास से मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई थी, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा है कि उसने अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज के उद्देश्य से पंच गवाह के रूप में भी काम किया था। दूसरा पंच गवाह प्रताप हालांकि उपलब्ध था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा किसी कारण से पूछताछ नहीं की गई। इसलिए, जहां तक अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की बरामदगी का संबंध है, अब हमारे पास जांच अधिकारी के साक्ष्य बचे हैं। हम कानून की स्थिति के प्रति सचेत हैं कि भले ही खोज पंचनामा के स्वतंत्र गवाहों की जांच न की जाए या यदि खोज के समय कोई गवाह मौजूद नहीं था या यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं था, तो कानून के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित करना मुश्किल है, कि दस्तावेज द्वारा तैयार किया गया पुलिस अधिकारी द्वारा दागी के रूप में माना जाना चाहिए और खोज साक्ष्य अविश्वसनीय होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को जांच अधिकारी के साक्ष्य पर विचार करना होगा, जिसने अभियुक्त से प्राप्त बयान के आधार पर खोज के तथ्य को प्रस्तुत किया था।

55. कानून के पूर्वोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हम जांच अधिकारी के साक्ष्य को न केवल अविश्वसनीय पाते हैं, बल्कि हम यह कहने की हद तक जा सकते हैं कि यह कानूनी साक्ष्य नहीं है।

26. **सुब्रमण्य (सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 76 से 78 में निम्नानुसार अवलोकन किया है: -

76. पूर्वोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष कानून के अनुसार खोजों को साबित करने और स्थापित करने में सक्षम है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार है:

"27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी की कितनी साबित हो सकती है :-

परन्तु जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप खोजे गए किसी तथ्य के रूप में कोई तथ्य अभिव्यक्त किया जाता है तो ऐसी इतनी अधिक सूचना, चाहे वह संस्वीकृति के समान हो या नहीं, जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से सुस्पष्ट रूप से संबंधित हो, सिद्ध की जा सकेगी।"

77. पूर्वोक्त अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के साक्ष्य में पहली और बुनियादी दुर्बलता यह है कि उनमें से किसी ने भी अपीलकर्ता द्वारा यहां दिए गए सटीक बयान को पेश नहीं किया है, जिसके कारण अंततः साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रासंगिक तथ्य की खोज हुई।

78. यदि, जांच अधिकारी के बारे में यह कहा जाता है कि आरोपी अपीलकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर हिरासत में रहते हुए एक बयान दिया कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने अपराध का हथियार, शव को दफनाने की जगह, कपड़े आदि छिपाए थे, तो पहली बात यह है कि जांच अधिकारी को पुलिस स्टेशन में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए था। एक बार जब दो स्वतंत्र गवाह अपनी उपस्थिति में पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, तो आरोपी को उचित बनाने के लिए कहा जाना चाहिए उस स्थान को इंगित करने के संबंध में जैसा वह चाहता है, जहां उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपराध के हथियार आदि को छिपाया है। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष इस तरह का बयान देता है, तो सटीक बयान या अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो जांच अधिकारी कानून के अनुसार निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि यह विश्वास किया जा सके कि अभियुक्त द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा से उस स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक विशेष बयान दिया गया था जहां अपराध के हथियार या अपराध के कमीशन में किसी अन्य वस्तु का उपयोग किया गया था छुपाया गया था। एक बार पंचनामा का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद, पुलिस पार्टी आरोपी और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाह) के साथ आरोपी के नेतृत्व में विशेष स्थान पर आगे बढ़ेगी। यदि उस विशेष स्थान से कुछ भी अपराध के हथियार या खून से सने कपड़े या किसी अन्य वस्तु की खोज की जाती है, तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामा का दूसरा हिस्सा होगा। इस तरह कानून जांच अधिकारी से अपेक्षा करता है कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज पंचनामा तैयार करे। अगर हम जांच अधिकारी के पूरे मौखिक साक्ष्य को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट है कि मामले के उपरोक्त सभी प्रासंगिक पहलुओं में इसकी कमी है।

27. विधि के पूर्वोक्त उपबंध को ध्यान में रखते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में, यदि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि जांच एजेंसी द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। आईओ या अभियोजन पक्ष के किसी अन्य गवाह ने अपीलकर्ता राजेश कुमार गुप्ता द्वारा अपने इकबालिया बयान की रिकॉर्डिंग के समय इस्तेमाल किए गए सटीक शब्द के बारे में अदालत के समक्ष गवाही नहीं दी। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के कहने पर मृतक के शव की खोज को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, इस तरह की खोज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

28. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के सीडीआर के साथ-साथ अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों पर भी बहुत अधिक भरोसा किया है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि आईओ ने स्वीकार किया है कि उनके पास सीडीआर की मूल प्रति नहीं है। इसके अलावा, उनके बयान के अनुसार, संजय कुमार ने उन्हें सीडीआर की प्रति प्रदान की है। हालांकि, उक्त संजय कुमार से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। सीडीआर के संबंध में प्रविष्टियों वाली केस डायरी के कुछ पैराग्राफ, आश्चर्यजनक रूप से, न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मोबाइल कंपनी के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है और न ही साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी (4) के तहत जारी प्रमाण पत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया है।

29. इस प्रकार, हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने सीडीआर पर गलत तरीके से भरोसा किया है और अभियोजन अपीलकर्ताओं/दोषियों के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियोजन पक्ष ने प्रमुख ठोस सबूतों द्वारा मृतक को मारने के लिए अपीलकर्ताओं की ओर से मकसद साबित नहीं किया है। यह अच्छी तरह से तय है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, मकसद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **रवींद्र सिंह @ काकू (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 20 और 21 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"20. अंत में, इस अपील ने कानून का एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए कॉल रिकॉर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए और 65 बी के तहत स्वीकार्य होंगे, इस तथ्य को देखते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रमाणन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है जैसा कि अधिनियम के तहत विचार किया गया है। अनवर पीवी बनाम पीके बशीर और अन्य की अनिश्चितता; [(2014) 10 एससीसी 473] कानून के इस क्षेत्र में दायर पर कब्जा कर लेता है या क्या शफी मोहम्मद वी। हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 2 एससीसी 801 इस संबंध में सही कानून को निर्धारित करता है, जिसे अब इस न्यायालय द्वारा अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल [(2020) 7 एससीसी 1] में दिनांक 14/07/2020 के एक निर्णय द्वारा निर्णायक रूप से सुलझाया गया है, जिसमें अदालत ने माना है कि: इसलिए, हम दोहरा सकते हैं कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता है धारा 65B(4) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, जैसा कि अनवर पीवी (सुप्रा) में सही ढंग से आयोजित किया गया है, और शफी मोहम्मद (सुप्रा) में गलत तरीके से "स्पष्ट" किया गया है। इस तरह के प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि धारा 65 बी (4) कानून की अनिवार्य आवश्यकता है। दरअसल, टेलर वी। टेलर (1876) 1 Ch.D 426, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में पालन किया गया है, को भी लागू किया जा

सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) स्पष्ट रूप से कहती है कि माध्यमिक साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य है जब बताए गए तरीके से लीड किया जाए और अन्यथा नहीं। अन्यथा धारण करने के लिए धारा 65 बी (4) को समाप्त कर दिया जाएगा। अनवर पीवी (सुप्रा), जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर स्पष्ट किया गया है, इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी पर घोषित कानून है। टॉमासो ब्रूनो (सुप्रा) में निर्णय, प्रति इंकुरियम होने के नाते, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, 2011 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9431 में निर्णय को शफी मोहम्मद (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किया गया और 03.04.2018 के निर्णय को (2018) 5 एससीसी 311 के रूप में रिपोर्ट किया गया, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण यह है कि धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किया गया है। यह एक लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि एक मोबाइल फोन के मालिक द्वारा किया जा सकता है, गवाह बॉक्स में कदम रखकर और यह साबित करके कि संबंधित डिवाइस, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की जाती है, स्वामित्व और / या उसके द्वारा संचालित है। ऐसे मामलों में जहां "कंप्यूटर" "कंप्यूटर सिस्टम" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का एक हिस्सा होता है और इस तरह के सिस्टम या नेटवर्क को भौतिक रूप से लाना असंभव हो जाता है न्यायालय, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा 65 बी (1) के अनुसार हो सकता है, साथ में धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र भी हो सकता है।

21. उपर्युक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कानून के अनुसार होना चाहिए था और इसे कानून की अदालत में स्वीकार्य होने के लिए प्रमाणन आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए था। जैसा कि ऊपर ठीक ही कहा गया है, इस तरह के प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य, जैसा कि वर्तमान मामले में है, संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि धारा 65 बी (4) कानून की अनिवार्य आवश्यकता है।

30. यह बचाव पक्ष का विशिष्ट मामला है कि अभियोजन पक्ष ने संजय कुमार, नोडल अधिकारी, रमाकांत, पुलिस कांस्टेबल, उन गवाहों की जांच नहीं की, जिन्होंने पूछताछ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह, उक्त गवाहों की गैर-परीक्षा के कारण, अभियुक्त के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

31. सुजीत बिस्वास (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर, यह अच्छी तरह से तय है कि संहिता की धारा -313 के तहत बयान दर्ज करते समय अभियुक्त के सामने नहीं रखी गई परिस्थितियों का उपयोग अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। पूर्वोक्त निर्णय का पैरा -12 निम्नानुसार है:

“12. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि एक आपराधिक मुकदमे में, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी व्यक्ति की जांच करने का उद्देश्य, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा करना है, अर्थात् ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका मतलब यह है कि अभियुक्त को उसके साथ जुड़ी आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, और अदालत को इस तरह के स्पष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए। परिस्थितिजन्य के मामले में साक्ष्य, यह तय करने के लिए आवश्यक है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है या नहीं। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य कितने भी कमजोर क्यों न हों, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त से पूछताछ करे और उसके खिलाफ सामने आई आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में उसका स्पष्टीकरण मांगे। जिन परिस्थितियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त की परीक्षा में नहीं रखा गया है, उनका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है और उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। उक्त कथन को भीतर साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का अर्थ, क्योंकि अभियुक्त को इस तरह के बयान के संदर्भ में जिरह नहीं की जा सकती है।

32. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए ठोस सबूत देकर परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया है। इसलिए, इसे रद्द करने और अलग रखने के योग्य है।

33. तदनुसार, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, खगड़िया द्वारा 2010 के सत्र परीक्षण संख्या 395 (2010 के खगड़िया मुफ्फसिल थाना प्रकरण संख्या 118 से उत्पन्न) के संबंध में दिनांक 28.02.2014 को दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश दिनांक 05.03.2014 को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

33.1. अपीलकर्ता, अर्थात् माला देवी, (2014 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 368), हिरासत में है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अगर किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा किया जाए।

33.2. अपीलकर्ता, अर्थात् राजेश कुमार गुप्ता, (2014 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 297 में) जमानत पर है। उसे अपने जमानत-बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

34. अपील की अनुमति दी जाए।

(विपुल एम. पंचोली, जे)

(रमेश चंद मालवीय, जे)

K.C.Jha/ -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।